महाराष्ट्र में BJP सरकार के सामने होगी गन्ने की मुश्किल

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सरकार अगर बुधवार को विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहती है तो उसके सामने पहली बड़ी चुनौती इसी सप्ताह होने वाली शुगरकेन प्राइस कंट्रोल बोर्ड (एसपीसीबी) की मीटिंग को लेकर होगी। अगर बोर्ड गन्ने की कीमत के मुद्दे पर सहमति के साथ कोई हल निकालने में सफल रहता है तो यह देश में चीनी का सबसे अधिक प्रॉडक्शन करने वाले इस राज्य की शुगर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इससे पहले राज्य सरकार गन्ने की कीमत तय करने के लिए मिलों और किसान संगठनों के बीच मध्यस्थ का काम करती थी। यह चलन दो वर्ष पहले बंद कर दिया गया और पिछले वर्ष एसपीसीबी का गठन किया गया था। बोर्ड ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है।कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र इस तरह का बोर्ड बनाने वाला दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश की मिलें ऊंचे स्टेट एडवाइजरी प्राइसेज की समस्या दूर करने के लिए एसपीसीबी बनाने की मांग कर रही हैं। मिलों का कहना है कि गन्ने की कीमत ज्यादा होने के चलते उन पर किसानों की बकाया रकम बढ़ रही है।

सरकार के सामने पहली बड़ी चुनौती इसी सप्ताह होने वाली शुगरकेन प्राइस कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग को लेकर होगी

महाराष्ट्र के एसपीसीबी की इस सप्ताह मीटिंग होने की संभावना है, लेकिन बोर्ड के लिए प्राइस तय करना आसान नहीं होगा। चीनी की कम कीमतों की वजह से मिल मालिक सीजन की शुरुआत में ही ज्यादा प्राइस नहीं देना चाहते, लेकिन किसान इसे बढ़ाने के लिए दबाव डालेंगे।

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की पूर्ति शुगर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर दिवे ने कहा, 'एसपीसीबी का गठन रंगराजन कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया है और कमेटी का कहना है कि गन्ने के भुगतान की पहली किस्त के तौर पर चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से तय फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस (एफआरपी) देना जरूरी है। हालांकि, एफआरपी देना मुश्किल है, लेकिन सभी मिलों को यह देना होगा।'

गन्ने की ऊंची कीमत के लिए आवाज उठाने में सबसे आगे रहने वाले स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी राज्य में बीजेपी सरकार का हिस्सा हैं।

Economic Times

12/11/14